Part XIX: Miscellaneous

Part XIX of the Constitution of India deals with Miscellaneous provisions. It contains various miscellaneous provisions that do not fit into any of the other Parts of the Constitution.

Article 360 provides for the proclamation of financial emergency by the President, on the grounds of threatened financial stability or credit of India. When a financial emergency is proclaimed, the President can give directions to the States regarding the manner in which the executive power thereof is to be exercised.

Article 361 provides for the protection of the President and Governors of States against any civil or criminal proceedings in respect of things done or omitted to be done by them in the exercise of their functions.

Article 362 provides for the continuance of the laws in force immediately before the commencement of the Constitution, until altered or repealed or amended by a competent legislature or other competent authority.

Article 363 provides for the determination of disputes between the Union and one or more States.

Article 364 provides for the adequacy of financial resources of the Union and the States.

Article 365 provides for the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every State is carried on in accordance with the provisions of the Constitution.

Article 366 defines certain expressions used in the Constitution.

Article 367 provides for the interpretation of the Constitution.

Overall, Part XIX of the Constitution of India contains various miscellaneous provisions that do not fit into any of the other Parts of the Constitution, and lays down provisions regarding financial emergency, protection of the President and Governors, continuance of laws, determination of disputes, and interpretation of the Constitution.

भाग XIX: विविध

भारत के संविधान का भाग XIX विविध प्रावधानों से संबंधित है। इसमें विभिन्न विविध प्रावधान शामिल हैं जो संविधान के किसी भी अन्य भाग में फिट नहीं होते हैं।

अनुच्छेद 360 संकटग्रस्त वित्तीय स्थिरता या भारत की साख के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान करता है। जब एक वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो राष्ट्रपति राज्यों को उस तरीके के बारे में निर्देश दे सकता है जिसमें कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाना है।

अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को उनके कृत्यों के निर्वहन में उनके द्वारा की गई या छोड़ी गई बातों के संबंध में दीवानी या फौजदारी कार्यवाही से संरक्षण प्रदान करता है।

अनुच्छेद 362 संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू कानूनों को तब तक जारी रखने का प्रावधान करता है, जब तक कि सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता है।

अनुच्छेद 363 संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच विवादों के निर्धारण का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 364 संघ और राज्यों के वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 365 प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से बचाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है, संघ के कर्तव्य का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 366 संविधान में प्रयुक्त कुछ अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है।

अनुच्छेद 367 संविधान की व्याख्या के लिए प्रदान करता है।

कुल मिलाकर, भारत के संविधान के भाग XIX में विभिन्न विविध प्रावधान शामिल हैं जो संविधान के किसी भी अन्य भाग में फिट नहीं होते हैं, और वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति और राज्यपालों की सुरक्षा, कानूनों की निरंतरता, विवादों का निर्धारण, और संविधान की व्याख्या।